what are the reasons therefor and under what circumstances the connections were issued to them;

(d) the details of unauthorised bungalows which have so far been demolished and what is the position of other unauthorised bungalows; and

(e) what action has been taken against MCD officers who allowed the construction or did not take any action when the constructions were going on?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (e) Information is being collected and will be submitted to the Sabha.

Integrated Programme for low cost Sanitation

2260. SRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Rs. 189.02 crores integrated programme for low cost sanitation has been launched;

(b) if so, the salient features thereof;

(c) whether any complaints have been received regarding embezzlement of low cost sanitation funds given to different States, during 1990-91, 1991-92 and 1992-93 especially in respect of Bihar and Uttar Pradesh; and

(d) if so, what are the details thereof and steps taken in respect of these complaints?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) Yes, Sir. The Government of India has sanctioned Rs. 189.92 crores involving a number of sanitation projects under the integrated programme of Low Cost Sanitation for the Liberation of Scavengers. Under the programme more than two lakh dry latrines have been converted and more than 3.5 lakh new units constructed where no sanitation facility existed earlier.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

2261. [Transferded to 18th March, 1993]

Acquiring Cultiable Land for Non-Agricultural purposes

2262. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Government has recently made it mandatory to all concerned departments to seek the permission of the land Utilisation Board prior to acquiring cultivable land for non-agricultural purposes;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether other State Governments have been advised by the Central Government to do the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) The Ministry of Agriculture have informed that the Government of Uttar Pradesh have issued the orders to all concerned Departments in the States to obtain the permission of State Land Use Boards (SLUBs) prior to acquiring cultivable land for non-agricultural purposes. For this purposes, SLUB has issued guidelines that concerned Department should ensure that

such proposals should fulfil all the requisite condition required under the provision.

(c) Central Government has been advising State Governments from time to time SLUB should vigilantly and Critically watch the diversion of cultivable land to non-agricultural purposes. National Land Use & Conservation Board (NLCB) has formulated National Land Use Policy Outline (NLPO) and recommended to the States for implementation.

आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) में धीमी गति से कार्य

2263. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ठेकेदारों द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण आवास तथा शहरी विकास निगम अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया है ;

(ख) यदि हां, तो इन ठेकेदारों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) ऐसे ठेकेदारों को कोई कार्य न देने हेतु सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार कर रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) हुडको मुख्यत: विभिन्न आवास और शहरी अधसरंचना योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों आदि को ऋण सहायता देने में लगा हुआ है। ठेकेदारों द्वारा वास्तविक निर्माण सुनिश्चित करने और इन योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व ऋण लेने वाले अभिकरणों/राज्य सरकारों का है। हुडको केवल वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करना है और हुडको की इन योजनाओं के निर्माण क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं है।

करोल बाग क्षेत्र में अवैध निर्माण

2264. **श्री दिग्विजय सिंह :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :
श्री चतुरानन मिश्र :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य दिल्ली के करौल बाग क्षेत्र में धराशाई हुए चार मंजिले भवन की मरम्मत के नाम पर स्थानीय पुलिस और दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों की मिली भगत से अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए उक्त भवन के निर्माता ने दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों को घूस दी थी;

(ग) क्या इस क्षेत्र के रिहायशी परिसरों को व्यावसायिक परिसरों में परिवर्तित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली पुलिस ने बताया है कि अनधिकृत निर्माण में उनके कर्मचारियों की कोई मिलीभगत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने यह भी सूचित किया है कि जहां तक दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का संबंध है, अभी तक रिश्वत का कोई प्रमाण नहीं है।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम के अनुसार ऐसे निर्माण स्थगनादेशों की आड़ में तथा स्वीकृत भवन नक्शों का उल्लंघन करके किए जाते हैं। तथापि